उच्च न्यायालय पटना में

2017 की सिविल मिसेल्लेनीयस न्यायनिर्णयन सं. 96

==========

श्रीमती बिभा देवी, पत्नी- श्री मनोज कुमार पांडे और पुत्री- श्री गणपत शर्मा, निवासी- गांव धारकांधा, थाना- दावत और जिला- रोहतास।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

श्रीमती अन्नु देवी, पत्नी- श्री जगत निवाश, निवासी- गाँव- बैरैन, थाना- दौदनगर और जिला- औरंगाबाद।

..... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिती

याचिकाकर्ता/ओं के लिएः श्री मृगेंद्र कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिएः श्री मुरारी प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

श्री अरुण कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

==========

याचिका - माननीय न्यायाधीश, पालीगंज द्वारा टाइटल सूट संख्या 20/2014 में दिनांक 6.12.2016 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका, जिसमें माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर संशोधन याचिका को अस्वीकार कर दिया - याचिकाकर्ता, जो कि मूल वादी हैं, ने 2014 में टाइटल सूट संख्या 20 प्रारंभिक डिक्री हेतु दायर किया जिसमें संपत्ति में 1/3 हिस्सा मांगा और वादी के पक्ष में मुकदमे की लागत की

मांग की - याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन करने हेतु आवेदन दायर किया जिसे ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि मुकदमे का परीक्षण पहले ही प्रारंभ हो गया है और गवाहों की जाँच हो चुकी है, इसलिए संशोधन याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान से बाधित है - अस्वीकृति का आधार यह था कि प्रस्तावित संशोधन से मुकदमे का स्वरूप बदल सकता है - वादी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की पुत्री हैं, संयुक्त परिवार की एक महिला सदस्य हैं, और संयुक्त परिवार की संपत्ति या पूर्वजों के संबंध के बारे में सही जानकारी नहीं रखतीं - प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से केवल वंशावली तालिका को सही करने और संपत्ति का विवरण संशोधित करने का प्रयास किया गया था - यह कहना अनुचित होगा कि संशोधन से मुकदमे का स्वरूप बदलेगा - मुकदमा विभाजन के लिए दायर किया गया था और स्पष्टता लाने हेतु संशोधन आवश्यक थे - याचिकाकर्ता एक महिला हैं और संपत्ति या संबंधों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है - इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने देरी और परीक्षण प्रारंभ होने के आधार पर संशोधन अस्वीकार कर दिया - यह मुकदमे का स्वरूप बदल देगा - यदि प्रतिपक्ष को लागत के रूप में मुआवजा दिया जा सकता है तो संशोधन की अनुमति दी जा सकती है - यह विभाजन का मुकदमा है - कोई अन्य राहत नहीं मांगी गई, केवल संपत्ति का विवरण संशोधित किया गया है - ट्रायल कोर्ट की यह धारणा कि संशोधन से मुकदमे का स्वरूप बदलेगा, गलत है - यदि संशोधन की अनुमति नहीं दी गई तो मुकदमेबाजी में वृद्धि होगी - संशोधन आवश्यक प्रतीत होते हैं ताकि पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद का समाधान किया जा सके - ट्रायल कोर्ट ने संशोधन याचिका को अस्वीकार करके गलती की - यह आदेश कानून की दृष्टि में अस्थिर है - इसे 10,000 रुपये की राशि का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को करने की शर्त पर रद्द किया जाता है, जो निर्णय के बाद पहले दिन देय होगा - याचिका स्वीकृत की जाती है - विरोधी प्रतिवादियों को संशोधित लिखित बयान दाखिल कर वादी के दावे का खंडन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा - वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा

ओरल जजमेंट

तारीखः 23-04-2024

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता को स्वीकार करने के बिंदु पर सुना और मैं वर्तमान याचिका को प्रवेश के चरण में ही निपटाने का इरादा रखता हूं।

2. यह तात्कालिक याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पालीगंज के विद्वान उप न्यायाधीश द्वारा टाइटल सूट संख्या 20/2014 में पारित दिनांक 06.12.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी/याचिकाकर्ता द्वारा दायर संशोधन याचिका को खारिज कर दिया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी है और उसने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए शीर्षक विभाजन वाद संख्या 20/2014 दायर किया है:

> "*(क) नीचे अनुसूची I और II में वर्णित वाद में संपत्तियों में वादी के 1/3 हिस्से के विभाजन के लिए प्रारंभिक डिक्री वादी के पक्ष में पारित की जाए और एक सर्वेक्षण जानने वाले अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करके वादी का*

एक अलग तख्ता बनाया जाए और अंतिम डिक्री की तैयारी पर वादी को अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से उसके अलग तख्ते पर कब्जा दिया जाए।

> *(ख) मुकदमे की लागत प्रतिवादियों के विरुद्ध वादी को दी जाएगी।*
>
> *(ग) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोष जिसका वादी हकदार पाया जाता है, वादी के पक्ष में पारित किया जाएगा।"*

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त विभाजन के मुकदमे में याचिकाकर्ता ने आदेश VI नियम 17 के साथ पठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) के तहत संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने 06.12.2016 के आदेश के तहत मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मुकदमे की सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है और वादी सहित तीन गवाहों की जांच की जा चुकी है और इस प्रकार, संशोधन याचिका संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान से प्रभावित हुई थी। इसके अलावा, अस्वीकृति का आधार यह था कि प्रस्तावित संशोधन से मुकदमे की प्रकृति बदलने की संभावना थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वादी/याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की बेटी है और वह वादी और प्रतिवादियों के संयुक्त परिवार की महिला सदस्य है तथा उसे संयुक्त परिवार की संपत्ति या पूर्वजों के संबंधों के बारे में सही जानकारी नहीं थी। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से, केवल वंशावली तालिका को सही करने की मांग की गई थी, तथा उसके बाद संपत्तियों के विवरण को भी संशोधित करने की मांग की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि संशोधन लाने से मुकदमे की प्रकृति बदल जाएगी क्योंकि मुकदमा विभाजन के लिए दायर किया गया था और केवल स्पष्टता लाने के लिए संशोधनों को शामिल करने की मांग की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि संशोधन बाद में लाए गए थे, लेकिन इसकी व्याख्या इस प्रकार की जाएगी कि

वादी/याचिकाकर्ता एक महिला है और उसे संपत्ति या संबंध के बारे में उचित जानकारी नहीं थी। संशोधन पेश करने में हुई देरी को समझाया जा सकता है और यदि न्यायालय को लगता है कि विचाराधीन मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए ऐसे संशोधन आवश्यक थे, तो उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता ने **भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स (पी) लिमिटेड** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं, जो **2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1128** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि पक्षों के बीच विवाद के प्रभावी और उचित निर्णय के लिए यह आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो निश्चित रूप से इससे मुकदमेबाजी की बहुलता हो जाएगी क्योंकि वादी/याचिकाकर्ता को उन संपत्तियों के बंटवारे के लिए एक और मुकदमा लाने का अधिकार होगा, जिनका उल्लेख मूल मुकदमे में किया जाना बाकी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त संशोधन से मुकदमे की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने कानून की कुछ गलत धारणा के तहत माना है कि इस संशोधन के माध्यम से मुकदमे की प्रकृति बदल जाएगी।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क का पुरजोर विरोध किया। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि संशोधन याचिका बहुत बाद में दायर की गई है, जब मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है। ऐसी याचिका संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान से प्रभावित थी, जो मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन पर रोक लगाती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता उचित परिश्रम दिखाने में विफल रही है। याचिकाकर्ता को पहले से ही अपने पिता की संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी थी और उसने अपने दुल्हिन बाजार गैर-एफआईआर संख्या 05/2013 पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में मुकदमे की संपत्ति

का विवरण दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से जानबूझकर लापरवाही बरती गई है। विद्वान वकील ने दोहराया कि यह उचित परिश्रम का मामला नहीं है। वादी की ओर से चार गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है, जिसमें वादी भी शामिल है और इस स्तर पर संशोधन की अनुमति देने से प्रतिवादी/प्रतिवादी के मामले पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, विद्वान वकील का कहना है कि वर्तमान याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

6. मैंने पक्षकारों के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतिकरण तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गहन विचार किया है। पक्षकारों की प्रस्तुतिकरण पर विचार करने से पहले, सी.पी.सी. के आदेश VI नियम 17 के तहत संशोधन के प्रावधानों पर गौर करना लाभदायक होगा, जो इस प्रकार है:

> "***17. दलीलों में संशोधन.***-- *न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार को अपनी दलील को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जो न्यायसंगत हों, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों:*
>
> *बशर्ते कि सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि समुचित तत्परता के बावजूद पक्षकार सुनवाई शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।*"

7. इस बिंदु पर कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा तय किया गया है और मामलों की उस श्रृंखला में, **भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव**

बिल्डर्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) का मामला है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 70 में संशोधन के बिंदु पर कानून को निम्नलिखित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत किया है:

> "***70.*** *हमारे अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार संक्षेपित किए जा सकते हैं:*
>
> *(i) सीपीसी का आदेश II नियम 2 किसी बाद के मुकदमे के विरुद्ध एक निषेध के रूप में कार्य करता है यदि इसके आवेदन के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी होती हैं और दलीलों में संशोधन का क्षेत्र इसके दायरे से बहुत दूर है। इस प्रकार, सीपीसी के आदेश II नियम 2 के तहत संशोधन पर रोक लगाने की दलील गलत है और इसलिए इसे नकार दिया गया है।*
>
> *(ii) सभी संशोधनों को अनुमति दी जानी चाहिए जो विवाद में वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं, बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या पूर्वाग्रह न हो। यह अनिवार्य है, जैसा कि सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्द्ध में "करेगा" शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है। (iii) संशोधन के लिए प्रार्थना को अनुमति दी जानी चाहिए*
>
> *(i) यदि संशोधन पक्षों के बीच विवाद के प्रभावी और उचित निर्णय के लिए आवश्यक है, और*
>
> *(ii) कार्यवाहियों की बहुलता से बचने के लिए, बशर्ते*
>
> *(क) संशोधन से दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होता,*
>
> *(ख) संशोधन द्वारा, संशोधन चाहने वाले पक्ष, पक्ष द्वारा की गई किसी स्पष्ट स्वीकृति को वापस लेने की मांग नहीं करते हैं जो दूसरे पक्ष को अधिकार प्रदान करती है और*

(ग) संशोधन समय बाधित दावा नहीं उठाता है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को मूल्यवान उपार्जित अधिकार (कुछ स्थितियों में) से वंचित होना पड़ता है ।

(iv) संशोधन के लिए प्रार्थना को आम तौर पर तब तक अनुमति दी जानी आवश्यक है जब तक कि

(i) संशोधन द्वारा, समय बाधित दावा प्रस्तुत किया जाना चाहा जाता है, ऐसी स्थिति में यह तथ्य कि दावा समय बाधित होगा, विचारणीय एक प्रासंगिक कारक बन जाता है,

(ii) संशोधन से मुकदमे की प्रकृति में परिवर्तन होता है,

(iii) संशोधन की प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है, या

(iv) संशोधन से, दूसरा पक्ष वैध बचाव खो देता है।

(v) दलीलों में संशोधन के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय, न्यायालय को अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, तथा सामान्यतः उदारता बरतने की अपेक्षा की जाती है, विशेषकर जहां विरोधी पक्ष को लागतों से मुआवजा दिया जा सकता हो।

(vi) जहां संशोधन से न्यायालय को विवाद पर सटीक विचार करने में सहायता मिलेगी तथा अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सहायता मिलेगी, वहां संशोधन की प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए।

(vii) जहां संशोधन में समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई अतिरिक्त या नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की मांग की गई हो, वहां संशोधन को समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी अनुमति दी जा सकती है।

(viii) संशोधन की अनुमति न्यायोचित रूप से दी जा सकती है, जहां इसका उद्देश्य वादपत्र में भौतिक विवरणों की अनुपस्थिति को सुधारना हो।

(ix) संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी अकेले प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां देरी का पहलू बहस योग्य है, वहां संशोधन के लिए प्रार्थना को अनुमति दी जा सकती है और सीमा के मुद्दे को निर्णय के लिए अलग से तैयार किया जा सकता है।

(x) जहां संशोधन वाद की प्रकृति या वाद के कारण को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि वादपत्र में स्थापित मामले से भिन्न एक पूर्णतया नया मामला स्थापित हो जाए, वहां संशोधन को अस्वीकृत किया जाना चाहिए। तथापि, जहां वांछित संशोधन केवल वादपत्र में दिए गए अनुतोष के संबंध में है, तथा उन तथ्यों पर आधारित है जो वादपत्र में पहले ही अभिवचनित किए जा चुके हैं, वहां सामान्यतः संशोधन की अनुमति अपेक्षित होती है।

(xi) जहां परीक्षण शुरू होने से पहले संशोधन की मांग की जाती है, वहां न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में उदार होना चाहिए। न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि संशोधन में स्थापित मामले को पूरा करने के लिए विरोधी पक्ष को एक मौका मिलेगा। इस प्रकार, जहां संशोधन के परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष को अपूरणीय नुकसान नहीं होता है, या विरोधी पक्ष को उस लाभ से वंचित नहीं करता है जो उसे संशोधन की मांग करने वाले पक्ष द्वारा स्वीकारोक्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था, वहां संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। समान रूप से, जहां न्यायालय के लिए पक्षों के बीच विवाद में मुख्य मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए संशोधन

आवश्यक है, वहां संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। (विजय गुप्ता बनाम गगनिंदर कुमार गांधी, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 1897 देखें)"

8. वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने देरी और ट्रायल शुरू होने के आधार पर संशोधन याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और इस आधार पर भी कि संशोधन से मुकदमे की प्रकृति बदल जाएगी।

9. इस न्यायालय द्वारा **अब्दुल समद बनाम शुकदेव महतो एवं अन्य (सिविल विविध संख्या 1744/2019)** के मामले में मुकदमे की शुरूआत पर चर्चा की गई है और इसका अलग अर्थ है। आमतौर पर शुरूआत को उस तारीख से समझा जाता है जब मुद्दे सुलझा लिए जाते हैं और सबूत शुरू होते हैं। हालांकि, कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बलदेव सिंह एवं अन्य बनाम मनोहर सिंह एवं अन्य** के मामले में, **(2006) 6 एससीसी 498** में रिपोर्ट किया है कि संहिता के आदेश 6 नियम 17 के प्रावधान में इस्तेमाल किए गए मुकदमे की शुरूआत को सीमित अर्थ में समझा जाना चाहिए, जिसका अर्थ मुकदमे की अंतिम सुनवाई, गवाहों की जांच, दस्तावेजों को दाखिल करना और दलीलें पेश करना है। साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संहिता के आदेश 6 नियम 17 का प्रावधान न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी चरण में लिखित बयान में संशोधन की अनुमति देने के लिए व्यापक शक्ति और अप्रतिबंधित विवेक प्रदान करता है। यहां तक कि प्रावधान भी अपवाद को स्वीकार करता है और इस आधार पर सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन की अनुमति देता है कि संशोधन के लिए आवेदन करने वाला पक्ष, उचित परिश्रम के बावजूद, सुनवाई शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था। वर्तमान मामले में, निस्संदेह सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन उचित समय के भीतर संशोधन को आगे न बढ़ाने के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, स्पष्टीकरण को इस साधारण कारण से स्वीकार किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को एक महिला बताया गया है और उसे उन सभी संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है जो अभी भी संयुक्त परिवार के कब्जे में हैं या यहां तक

कि उन संपत्तियों के बारे में भी जिन्हें निपटाया जा चुका है लेकिन गलत तरीके से वाद में संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में दिखाया गया है।

10. इसके अलावा, जहां तक प्रतिवादी के विद्वान वकील के इस तर्क का सवाल है कि याचिकाकर्ता को अपने पिता की संपत्तियों के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी थी और उसने अपने कहने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में मुकदमे की संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जो दुल्हिन बाजार गैर-एफआईआर संख्या 05/2013 है, विद्वान वकील धारा 144 सीआरपीसी कार्यवाही के दस्तावेजों से यह नहीं दिखा पाए हैं कि याचिकाकर्ता को संशोधन आवेदन में उल्लिखित संपत्तियों के विवरण के बारे में पहले से जानकारी थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता को पहले से जानकारी थी और उसने उचित परिश्रम नहीं किया।

11. मेरे सामने आए मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी के साक्ष्य के बाद संशोधन की मांग की गई है और चार गवाहों की जांच की गई है, लेकिन यह वादी का मुकदमा है और यदि कोई देरी होती है, तो अंततः वादी को ही नुकसान होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस स्तर पर संशोधन की अनुमति देने से दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा। हालांकि, अगर दूसरे पक्ष को लागत के मामले में मुआवजा दिया जा सकता है, तो संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, यह अदालत को तय करना है कि ऐसा संशोधन अदालत को पक्षों के बीच विवाद पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करने में सक्षम करेगा और सही निर्णय पर पहुंचने में मदद करेगा और विवाद में वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने की अनुमति देगा। इसके अलावा, अगर ऐसा संशोधन मुकदमेबाजी की बहुलता से बचता है, तो इन संशोधनों को अनुमति देने की आवश्यकता है।

12. इसके अलावा, संशोधन आवेदन के मात्र अवलोकन से मुझे नहीं लगता कि संशोधन की अनुमति देने से मुकदमे की प्रकृति बदल जाएगी। यह विभाजन का मुकदमा है

और कोई अन्य राहत नहीं मांगी गई है, केवल संपत्तियों के विवरण को संशोधित किया गया है। संशोधन के बाद भी, यह विभाजन का मुकदमा ही रहेगा। इसलिए, मुकदमे की प्रकृति में परिवर्तन के बारे में विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष के बारे में, मुझे लगता है कि यह गलत है। यदि संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इससे मुकदमेबाजी की अनावश्यक बहुलता हो जाएगी। संशोधन पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के निर्धारण के उद्देश्य से भी आवश्यक प्रतीत होते हैं। हालांकि, प्रतिवादी को अनुचित रूप से परेशान करने के लिए, मुझे लगता है कि के अनुसार प्रतिवादी को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

13. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, मुझे लगता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने संशोधन याचिका को स्वीकार करने से इनकार करके अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है और इसे खारिज कर दिया है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि 06.12.2016 का आदेश कानून की दृष्टि से टिकाऊ है और तदनुसार, इसे इस शर्त पर रद्द किया जाता है कि वादी द्वारा इस निर्णय के पारित होने के बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहली तारीख पर प्रतिवादी/प्रतिवादी को 10,000/- (केवल दस हजार) रुपये का भुगतान किया जाएगा। परिणामस्वरूप, विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर 07.09.2016 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. तथापि, प्रतिवादी को संशोधित लिखित बयान/अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करके वादी/याचिकाकर्ता के दावे का खंडन/विरोध करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

15. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि गुण-दोष पर कोई भी टिप्पणी केवल वर्तमान याचिका के निपटारे के संबंध में है और मैंने मुकदमे में दोनों पक्षों द्वारा अपनाए गए रुख के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और यह विचारण न्यायालय पर निर्भर है कि वह बिना ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए जल्द से जल्द मुकदमे का निपटारा अपने गुण-दोष के आधार पर करे क्योंकि यह 2014 का मामला है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के. पाण्डे/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।